



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-क

वर्ष ५, अंक ८१] शुक्रवार, डिसेंबर ६, २०१९/अग्रहायण १५, शके १९४१ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १२७

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर)
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त (राज्य उत्पादन शुल्क),
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील
इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो.

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ डिसेंबर २०१९

क्रमांक जीवका १५१९/प्र.क्र. ४७/नापु २३.— भारत सरकार, ग्राहक बाबी, अन्न व सावजनिक वितरण मंत्रालय, (ग्राहक बाबी विभाग) नवी दिल्ली यांच्याकडून असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-३, उपखंड (ii) मध्ये दिनांक ३ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रकाशित झालेली अधिसूचना खालीलप्रमाणे पुनःप्रकाशित करण्यात येत आहे :—

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सावजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक ३ दिसम्बर २०१९

का.आ. ४३४१ (अ).— केंद्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निबन्धन हटाना आदेश, २०१६ का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

(१) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निबन्धन हटाना (चौथा संशोधन) आदेश, २०१९ है।

(२) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

२. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थां से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निबधन हटाना आदेश, २०१६ के खण्ड ३ के उप-खण्ड (२) की मद (iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

“(iv) व्याज के संबंध में, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में व्यापारियों पर निम्नलिखित स्टॉक सीमाएं ;

थोक विनिमयता : २५ मीट्रिक टन तथा खुदरा विनिमयता : ५ मीट्रिक टन

बशर्त कि आयातक, जो थोक विनिमयता अथवा खुदरा विनिमयता अथवा डीलर है, को व्याज के आयातित स्टॉक के संबंध में छूट प्राप्त होगी .”

[फा.सं. एस-१०/३/२०१७-ईसीआरएण्डई],

रोहित कुमार परमार,
वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार.

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION
(Department of Consumer Affairs)**

Order

New Delhi, the 3rd December 2019

S.O. 4341 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby, makes the following Order to further amend the removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely :—

1. Short Title and Commencement.—

(1) This Order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Fourth Amendment) Order, 2019.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), the item (iv) is substituted by the following :—

“(iv) Onion with following stock limits on traders for all the States and Union Territories ;

Wholesaler : 25 MT and Retailer : 5 MT

Provided that an importer, being a wholesaler or retailer or dealer shall be exempted for the imported stock of onions.”

[F. No. S-10/3/2017-ECR and E],

ROHIT KUMAR PARMAR,
Senior Economic Adviser.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

सतिश सुपे,
शासनाचे सहसचिव.